



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 554]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसंबर 24, 1976/पौष 3, 1898

No. 554]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1976/PAUSA 3, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th December 1976

S.O. 828(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lockout in the services in the State of Kerala, connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply (including the works connected with the Idukki Hydro-electric Project in the State of Kerala) would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strike or lockout in the said services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits any strike or lockout, in connection with any industrial dispute in the said services for a period of six months with immediate effect.

[No. F. S.42011/3/76/DI(A)]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

अवस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का० सा० 828 (अ).—केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और केरल राज्य में जनता के लिए विद्युत् ऊर्जा प्रदाय से अथवा ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए (जिनके अन्तर्गत ये कार्य आते हैं जो केरल राज्य में इडिककी जल-विद्युत् परियोजना से सम्बन्धित हैं) विद्युत् के ऊर्जा के उत्पादन, संचयन या प्रेषण से सम्बन्धित सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, अतः उक्त सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त सेवाओं में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या तालाबन्दी को तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है ।

[नं० का० एस० 42011/3/76/डी-1(ए)]

डी० बंछोनाध्याय, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटों रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976